झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची

सिविल रिट याचिका सं० - 3080/2020

-----

1. मेसर्स जे.के. ब्रिक्स प्रोपराइटर रामदास साहू
2. मेसर्स मीना ब्रिक्स प्रोपराइटर नरेश साहू
3. मेसर्स ताज ब्रिक्स प्रोपराइटर मोहम्मद मुमताज खान उर्फ मुमताज अंसारी
4. मेसर्स एम.बी.सी. ब्रिक्स प्रोपराइटर मेराज अंसारी
5. आर.बी.सी. ब्रिक्स प्रोपराइटर संजीत प्रसाद
6. मेसर्स आर.बी.सी. ब्रिक्स प्रोपराइटर रंजीत साहू @ रंजीत कुमार साहू
7. मेसर्स जे. आर ब्रिक्स प्रोपराइटर जॉनसन रूंडा
8. मेसर्स केआरएमबी ब्रिक्स प्रोपराइटर राम कुमार
9. मेसर्स नोवा ब्रिक्स प्रोपराइटर जावेद अख्तर
10. मेसर्स चांद ब्रिक्स प्रोपराइटर मुमताज अहमद
11. मेसर्स नाम ब्रिक्स प्रोपराइटर दीपक कुमार साहू
12. मेसर्स सर्वश्री सेवक ब्रिक्स प्रोपराइटर अमर कुमार केशरी
13. मेसर्स शंकर ब्रिक्स प्रोपराइटर शंकर प्रसाद
14. मेसर्स नाथ ब्रिक्स प्रोपराइटर बैद्यनाथ साहू
15. शेखर ब्रिक्स प्रोपराइटर दीपक प्रसाद
16. भारत ब्रिक्स प्रोपराइटर किरण कुमारी
17. एम.बी.ए. ब्रिक्स प्रोपराइटर बाबूलाल महतो
18. आजाद ब्रिक्स प्रोपराइटर अब्दुल रब अंसारी
19. मेसर्स नैन ब्रिक्स प्रोपराइटर मोहम्मद मसूद अंसारी
20. टाइगर ब्रिक्स प्रोपराइटर राम प्रसाद साहू
21. मेसर्स बीएसपी ब्रिक्स प्रोपराइटर पंचम कुमार सिंह
22. मेसर्स टाइगर ब्रिक्स प्रोपराइटर ज्योति लाल शॉ
23. रवि ब्रिक्स प्रोपराइटर मोती लाल महतो
24. शक्ति ब्रिक्स प्रोपराइटर अशोक कुमार केशरी
25. मेसर्स जे.के. ब्रिक्स प्रोपराइटर संजय कुमार गुप्ता
26. पराग एंटरप्राइजेज प्रोपराइटर स्निग्ध अनुराग

27. मेसर्स सार्स ब्रिक्स प्रोपराइटर महाबीर कुमार @ महाबीर साहू
28. मेसर्स बी.के.बी. ब्रिक्स प्रोपराइटर मुखराम सिंह
29. माही ब्रिक्स प्रोपराइटर सिमंत कुमार
30. गुरु ब्रिक्स प्रोपराइटर अरुण कुमार सिंह @ अरुण सिंह
31. नीलू ब्रिक्स प्रोपराइटर गुरुचरण सिंह मुंजाल
32. स्टील ब्रिक्स फील्ड. पार्टनरशिप फर्म अशोक कुमार राय @ अशोक राय
33. मोहित ब्रिक्स प्रोपराइटर रमेश कुमार @ रमेश कुमार मुंजाल
34. रामा ब्रिक्स प्रोपराइटर लक्ष्मी नारायण केशरी
35. रमेश ब्रिक्स (आरबीएम) प्रोपराइटर अजय कुमार मेहता
36. रांची ब्रिक्स प्रोपराइटर संजय कुमार साहू
37. एस.आर.एम., ब्रिक्स प्रोपराइटर मनोज कुमार यादव
38. भारत ब्रिक्स प्रोपराइटर मनोज वर्मा
39. सन ब्रिक्स प्रोपराइटर मोहम्मद नसीम आलम
40. ए.बी.सी. ब्रिक्स प्रोपराइटर समीम अख्तर
41. अनिल ब्रिक्स प्रोपराइटर रामायण सिंह
42. मेसर्स एस.एम.बी. ब्रिक्स प्रोपराइटर शंकर साहू
43. फॉर नाज ब्रिक्स प्रोपराइटर अफरोज अंसारी
44. जे.एम.डी. ब्रिक्स प्रोपराइटर बिश्वनाथ साहू
45. मेसर्स सी.आर.डी. ब्रिक्स प्रोपराइटर मुकेश कुमार
46. रोमा ब्रिक्स प्रोपराइटर अब्दुल कुदुस @ अब्दुल कुदुस अंसारी
47. अम्मा ब्रिक्स प्रोपराइटर अयाज खान
48. मेसर्स एस.के.बी. ब्रिक्स प्रोपराइटर सदानंद साहू
49. बी.वी.एम. ब्रिक्स प्रोपराइटर बेनी साहू
50. फॉर फाइन ब्रिक्स प्रोपराइटर मोहम्मद मुमताज अंसारी
51. एस.आर.बी. ब्रिक्स प्रोपराइटर सुधीर कुमार सिंह
52. मीना ब्रिक्स प्रोपराइटर राज कुमार गुप्ता
53. मेसर्स ए.आर. ब्रिक्स प्रोपराइटर अपरेश नंदी
54. पूजा ब्रिक्स प्रोपराइटर उदय प्रताप सिंह
55. फॉर आर.के. ब्रिक्स प्रोपराइटर राज कुमार @ राज कुमार गुप्ता
56. मेसर्स जे.के. ब्रिक्स प्रोपराइटर बसंत कुमार

57. एस.आर.बी. ब्रिक्स प्रोपराइटर मो. इकबाल अंसारी @ मो. इकबाल
58. मेसर्स हिंद ब्रिक्स प्रोपराइटर सैय्यद इनामुल हक
59. पूजा ब्रिक्स प्रोपराइटर अनिल कुमार केशरी
60. आर.एल.एम. ब्रिक्स प्रोपराइटर मनीष कुमार
61. भवानी ब्रिक्स प्रोपराइटर धीरेन्द्र कुमार
62. बी.एम. ब्रिक्स, प्रोपराइटर राधो देवी
63. पवन ब्रिक्स, प्रोपराइटर लोदा ओरांव .... **याचिकाकर्ता**

-बनाम-

1. झारखंड राज्य
2. सचिव खान एवं भूविज्ञान विभाग, नेपाल हाउस, डाकघर + थाना - डोरंडा, जिला - रांची
3. जिला खनन पदाधिकारी, रांची, कोर्ट रोड, डाकघर - जी.पी.ओ., थाना - कोतवाली, जिला - रांची। .... **प्रतिवादी**

कोरम: माननीय जस्टिस श्री सुजीत नारायण प्रसाद
माननीय जस्टिस श्री नवनीत कुमार

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री कल्याण रॉय, अधिवक्ता
राज्य की ओर से : श्री मोहन दुबे, ए.सी. टू ए.जी.

10/दिनांक: 30.11.2023

1. यह रिट याचिकाकर्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कुल 63 रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई है, जिन्होंने अलग-अलग न्यायालय शुल्क जमा किए थे, जिसमें प्रतिवादी द्वारा जारी अनुलग्नक-1 श्रृंखला के रूप में संलग्न मांग नोटिस को रद्द करने के निर्देश की मांग की गई थी, जिसके द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट में संदर्भित निरीक्षण के आधार पर कम रॉयल्टी की गणना करने के निर्णय के परिणामस्वरूप मांग की गई थी।

2. रिट याचिका में की गई दलील के अनुसार मामले के संक्षिप्त तथ्य, जिनका उल्लेख किया जाना आवश्यक है, निम्नानुसार हैं:-

3. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे ईंटों का निर्माण करते थे और झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2017 के तहत पंजीकृत डीलर हैं।

4. अपने ईंट भट्टों के निरीक्षण के बाद याचिकाकर्ताओं ने ईंटों का निर्माण शुरू कर दिया और नियमित रूप से रिटर्न दाखिल करने और समय-समय पर रॉयल्टी का भुगतान भी करते थे। याचिकाकर्ता प्रति वर्ष लाखों ईंटों के निर्माण के हकदार हैं। अचानक, प्रतिवादी संख्या 2 ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ डिमांड नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें रॉयल्टी के भुगतान के लिए कुछ राशि जमा करने और जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया।

5. सभी रिट याचिकाकर्ताओं को रॉयल्टी और उस पर लगाए गए जुर्माने के कम भुगतान का दावा करते हुए डिमांड नोटिस जारी किए गए।

6. यह भी मामला है कि याचिकाकर्ताओं ने निर्मित ईंटों की संख्या पर रॉयल्टी की पूरी राशि जमा कर दी है। मांग नोटिस (अनुलग्नक-1 श्रृंखला) से यह पता चलता है कि ऐसी मांग विभाग द्वारा किए गए निरीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर उठाई गई थी।

7. यह कहा गया है कि प्रतिवादियों द्वारा निरीक्षण की तिथि के बारे में कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है और बार-बार मांग के बावजूद, प्रतिवादी संख्या 2 ने निरीक्षण रिपोर्ट या रॉयल्टी के कम भुगतान और लगाई गई राशि की गणना की विधि प्रदान नहीं की है।

8. आगे यह मामला है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने न तो कोई निरीक्षण रिपोर्ट पेश की और न ही रॉयल्टी की राशि तय करने के उद्देश्य से जे.एम.एम.सी. नियमों के नियम 41 के अनुसार सुनवाई की कोई तारीख या स्थान तय किया।

9. उक्त नोटिस से पता चलता है कि खान निरीक्षक ने अपनी दिनांक 18.01.2019 की रिपोर्ट में संकेत दिया है कि भट्ठा मालिक ने रॉयल्टी जमा नहीं की है और वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए लाइसेंस प्राप्त नहीं किया है और भट्ठा चलाना शुरू कर दिया है। याचिकाकर्ताओं को किसी भी समय दिनांक 18.01.2019 की कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई है।

10. दिनांक 18.01.2019 की रिपोर्ट में यह कहीं भी नहीं दर्शाया गया कि याचिकाकर्ताओं ने जे.एम.एम.सी. नियमों के नियम 30 और 32 का उल्लंघन किया है। यह भी कहीं नहीं बताया गया कि याचिकाकर्ता रॉयल्टी का भुगतान किए बिना और बिना किसी लाइसेंस के अपने भट्टे का संचालन कर रहे हैं।

11. तथ्यात्मक पहलू से यह स्पष्ट है कि रिट याचिकाकर्ता ईंटों के निर्माण का व्यवसाय कर रहे हैं और झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियम, 2017 के तहत पंजीकृत डीलर हैं।

12. रिट याचिकाकर्ताओं की शिकायत है कि एक निरीक्षण के आधार पर, डिमांड नोटिस इस तथ्य के आधार पर जारी किए गए हैं कि एक या दूसरे रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से जमा की गई राशि रॉयल्टी के संबंध में कम है।

13. इस रिट याचिका को दायर करने का आधार यह है कि निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति, जो डिमांड नोटिस जारी करने का आधार है, रिट याचिकाकर्ताओं को कभी नहीं दी गई और इस प्रकार उन्हें अपना बचाव प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान नहीं किया गया, इसलिए रिट याचिका दायर की गई है।

14. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि चूंकि निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति किसी एक या अन्य रिट याचिकाकर्ता द्वारा कम रॉयल्टी के आधार पर मांग उठाने से पहले उपलब्ध नहीं कराई गई है, इसलिए निरीक्षण रिपोर्ट की आपूर्ति न करना, जहां तक उक्त मांगों की गणना का संबंध है, स्वयं का बचाव करने के लिए पर्याप्त और पर्याप्त अवसर होने के सिद्धांत के विपरीत है।

15. राज्य ने जवाबी हलफनामा दाखिल करके रिट याचिका में की गई प्रार्थना का विरोध किया है।

16. हालांकि, प्रतिवादी राज्य की ओर से उपस्थित ए.सी. टू ए.जी. श्री मोहन दुबे ने यह तर्क दिया कि निरीक्षण रिपोर्ट की आपूर्ति न किए जाने के तथ्य पर कोई विवाद नहीं है।

17. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा रिट याचिका में की गई दलीलों तथा प्रति-शपथपत्र पर भी गौर किया है।

18. रिट याचिका एक या दूसरे रिट याचिकाकर्ताओं के पक्ष में जारी किए गए मांग नोटिस को रद्द करने के लिए निर्देश देने के लिए है, जिसके तहत

समिति द्वारा की गई गणना के आधार पर जारी किए गए मांग नोटिस, रॉयल्टी की राशि की कम मांग के परिणामस्वरूप हैं।

19. हमने अनुलग्नक-1 श्रृंखला में संलग्न मांग नोटिसों से पाया है कि एक या दूसरे रिट याचिकाकर्ताओं को संबंधित मांग नोटिसों में उल्लिखित राशि का भुगतान एक सप्ताह के भीतर करने का निर्देश दिया गया है, ऐसा न करने पर प्रमाण पत्र कार्यवाही शुरू की जाएगी।

20. इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि प्राधिकरण ने एक या दूसरे रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि की मात्रा निर्धारित करके निर्णय लिया है और यदि इसका भुगतान नहीं किया जाएगा, तो परिणाम बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के तहत प्रमाण पत्र मामला दर्ज करने का होगा।

21. इसलिए, संबंधित रिट याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर प्रदान करना कानून की आवश्यकता है ताकि प्राकृतिक न्याय के प्रमुख सिद्धांत का पालन किया जा सके।

22. यही तर्क है जिसके आधार पर रिट याचिका दायर की गई है।

23. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा श्रीमती मेनका गांधी बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में दिए गए निर्णय में कानून को अच्छी तरह से स्थापित किया गया है, जिसकी रिपोर्ट (1978) 1 एससीसी 248 में दी गई है, जिसमें यह प्रस्ताव रखा गया है कि भले ही ऐसा कोई वैधानिक प्रावधान न हो जिसके तहत अवसर दिए जाने की आवश्यकता हो, लेकिन प्राकृतिक न्याय के प्रमुख सिद्धांत का पालन करने के लिए, संबंधित पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए, जिस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय पासपोर्ट अधिनियम की धारा 10(3) से निपटने के दौरान ऐसा निर्णय दिया गया है, जिसमें उक्त प्रावधान की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि पासपोर्ट जब्त करने से पहले सुनवाई का अवसर प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।

24. हालांकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त प्रावधान की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है, लेकिन यह प्रस्ताव रखा है कि भले ही वैधानिक प्रावधान में कोई प्रावधान या शर्त न हो, तब भी, संबंधित प्राधिकारी का यह

बाध्य कर्तव्य होगा कि वह कोई भी प्रतिकूल निर्णय लेने से पहले सुनवाई का अवसर प्रदान करे, तत्पर संदर्भ के लिए, उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ को संदर्भित किया जाना चाहिए, जो इस प्रकार है: -

I. "9. हम इस प्रश्न पर चर्चा कुछ सामान्य टिप्पणियों के साथ शुरू कर सकते हैं ताकि प्रशासनिक कानून के क्षेत्र में प्राकृतिक न्याय के बढ़ते महत्व पर जोर दिया जा सके। प्राकृतिक न्याय एक महान मानवीय सिद्धांत है जिसका उद्देश्य कानून में निष्पक्षता लाना और न्याय को सुरक्षित करना है और पिछले कुछ वर्षों में यह प्रशासनिक कार्रवाई के बड़े क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले व्यापक रूप से व्यापक नियम के रूप में विकसित हुआ है। बोर्थ-वाई-गेस्ट के लॉर्ड मॉरिस ने बेंथम क्लब के समक्ष अपने संबोधन में इस नियम के बारे में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बात की:

"मुझे लगता है कि हम हाल के समय में और विशेष रूप से प्रशासनिक कानून के क्षेत्र में जो कुछ किया गया है, उस पर गर्व कर सकते हैं, इन सिद्धांतों को लागू करके और लागू करके जिन्हें हम मोटे तौर पर प्राकृतिक न्याय के नाम से वर्गीकृत करते हैं। उनके आवेदन के बारे में कई परीक्षण समस्याएं अभी भी हल होनी बाकी हैं। लेकिन मैं पुष्टि करता हूं कि प्रशासनिक कार्रवाई का क्षेत्र केवल एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सिद्धांतों को लागू किया जाना है। न ही उन्हें केवल तभी लागू किया जाना चाहिए जब प्रक्रियात्मक विफलताएं दिखाई दें। क्या प्राकृतिक न्याय को 'राजसी' अवधारणा के रूप में वर्णित किया जा सकता है? मेरा मानना है कि यह है। क्या यह केवल एक अलंकारिक लेकिन अस्पष्ट वाक्यांश है जिसका उपयोग, जब आवश्यक हो, आश्वासन देने के लिए किया जा सकता है? मेरा मानना है कि यह इससे कहीं अधिक है। यदि इसे कार्रवाई में निष्पक्षता के रूप में संक्षेपित किया जा सकता है - तो कौन चाहेगा कि यह कभी कार्रवाई से बाहर हो? यह दर्शाता है कि कानून को न केवल तर्क और तर्क द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा; इसमें अधिक उच्च प्रेरणा का अभाव है।

और फिर, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपने भाषण में वाइजमैन बनाम बोर्नमैन में, विद्वान लॉ लॉर्ड ने प्रेरित खुशी के शब्दों में कहा:

"... यह कि प्राकृतिक न्याय की अवधारणा सभी चरणों में न्यायिक कार्यों का निर्वहन करने वालों का मार्गदर्शन करे, न केवल स्वीकार्य है बल्कि कानून के दर्शन का एक अनिवार्य हिस्सा है। हम अक्सर प्राकृतिक न्याय के नियमों की बात करते हैं। लेकिन उनके बारे में कुछ भी कठोर या यांत्रिक नहीं है। वे जो समझते हैं उसका विश्लेषण और वर्णन कई अधिकारियों द्वारा किया गया है। लेकिन किसी भी विश्लेषण में परिभाषा की सटीकता या आवेदन के रूप में सटीकता की तुलना में उनकी भावना और उनकी प्रेरणा को राहत मिलनी चाहिए। हम ऐसे नुस्खों की तलाश नहीं करते हैं जो यह निर्धारित करेंगे कि विभिन्न भिन्न परिस्थितियों में क्या किया जाना चाहिए। उन सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को लागू किया जाना चाहिए जो किसी विशेष स्थिति या परिस्थितियों के समूह में सही और न्यायसंगत और निष्पक्ष हों। प्राकृतिक न्याय, यह कहा गया है, केवल 'कार्रवाई में निष्पक्ष खेल' है। न ही हम संसद से निर्देशों की प्रतीक्षा करते हैं। सामान्य कानून में प्रचुर संपदा है: हम वह पा सकते हैं जिसे बायल्स, जे. ने 'सामान्य कानून का न्याय' कहा है।

इस प्रकार, प्राकृतिक न्याय की आत्मा "कार्रवाई में निष्पक्षता" है और इसीलिए इसे लोकतांत्रिक दुनिया भर में सबसे व्यापक मान्यता मिली है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, प्रशासनिक सुनवाई के अधिकार को मौलिक निष्पक्षता की अनिवार्य आवश्यकता माना जाता है। और इंग्लैंड में भी यह माना गया है कि "कार्रवाई में निष्पक्षता" की मांग है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी पक्षपातपूर्ण या प्रतिकूल कार्रवाई करने से पहले उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। लॉर्ड डेनिंग, एमआर ने श्मिट बनाम राज्य सचिव या गृह मामलों में इस नियम को इन शब्दों में कहा था - "जहां एक सार्वजनिक अधिकारी के पास किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता या उसकी संपत्ति से वंचित

करने की शक्ति है, सामान्य सिद्धांत यह है कि उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना और अपनी ओर से प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिए बिना ऐसा नहीं किया जाना चाहिए"। यही नियम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड जैसे अन्य राष्ट्रमंडल देशों में भी लागू है। इसने संयुक्त राष्ट्र तक भी पहुँच प्राप्त कर ली है (देखें अमेरिकन जर्नल ऑफ़ इंटरनेशनल लॉ, खंड 67, पृष्ठ 479)। मैगरी, जे., प्राकृतिक न्याय को "कानून की उचित प्रक्रिया के आसवन के रूप में" वर्णित करते हैं (देखें फॉनटेन बनाम चैस्टारटन16)। यह न्याय की प्रक्रिया का सार है जो "कार्रवाई में निष्पक्षता" से प्रेरित और निर्देशित है। अगर हम वाइजमैन मामले में विभिन्न लॉ लॉर्ड्स के भाषणों को देखें तो यह देखा जाएगा कि उनमें से प्रत्येक ने यह सवाल पूछा था कि "क्या मामले की विशेष परिस्थितियों में, न्यायाधिकरण ने अनुचित तरीके से काम किया ताकि यह कहा जा सके कि उनकी प्रक्रिया न्याय की मांग से मेल नहीं खाती", या, क्या न्यायाधिकरण द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया "सभी परिस्थितियों में अनुचित थी?" प्रत्येक लॉ लॉर्ड द्वारा अपनाया गया परीक्षण यह था कि क्या अपनाई गई प्रक्रिया सभी परिस्थितियों में निष्पक्ष थी और "कार्रवाई में निष्पक्षता" के लिए यह आवश्यक था कि करदाता को "आयुक्तों के प्रति-बयान को देखने और उसका उत्तर देने का अवसर दिया जाना चाहिए" इससे पहले कि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि "उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है"। इसलिए, जांच हमेशा यह होनी चाहिए: क्या कार्रवाई में निष्पक्षता की मांग है कि प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए?

25. हमने कानून के उपरोक्त प्रस्ताव के आलोक में तथ्यात्मक पहलू की जांच की है और इस तथ्य का भी आकलन किया है कि यदि निरीक्षण रिपोर्ट नहीं दी गई है, तो क्या इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन कहा जा सकता है, जैसा कि रिट याचिका दायर करने में आधार लिया गया है।

26. इस न्यायालय ने, उपर्युक्त उद्देश्य के लिए, मांग नोटिस पर विचार किया है और पाया है कि मांग नोटिस का आधार ही निरीक्षण रिपोर्ट है, उक्त रिपोर्ट के निष्कर्ष के आधार पर, एक या दूसरे रिट याचिकाकर्ताओं पर

दायित्व डालते हुए मांग नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें एक सप्ताह के भीतर उक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है, ऐसा न करने पर प्रमाण पत्र कार्यवाही शुरू की जाएगी।

27. उक्त शर्त, विशेषकर राशि जमा न करने की स्थिति में प्रमाण पत्र कार्यवाही शुरू करने के परिणाम का अधिक महत्व है, क्योंकि बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के अनुसार, जिसमें धारा 3 में लोक मांग की परिभाषा दी गई है तथा लोक मांग की राशि का भुगतान न किए जाने की स्थिति में लोक पदाधिकारी के समक्ष मामला संस्थित कर कार्यवाही शुरू की जाएगी, तत्पश्चात अधिनियम, 1914 की धारा 7 के प्रावधान के आलोक में प्रमाण पत्र पदाधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा, जिसका अर्थ है कि एक बार प्रमाण पत्र कार्यवाही शुरू हो जाने के बाद, संबंधित व्यक्ति के पास उक्त मांग के संबंध में आपत्ति करने का एकमात्र उपाय उपलब्ध होगा। लेकिन, यह मामले का अलग पहलू है, क्योंकि उक्त अवसर तभी दिया जाएगा, जब प्रमाण पत्र कार्यवाही अधिनियम, 1914 की धारा 9 के तहत अपेक्षित आपत्ति दर्ज करने के माध्यम से शुरू की जाएगी।

28. लेकिन, यहां प्रश्न यह है कि रिट याचिका का विषय क्या है कि मांग का आधार क्या है और क्या रिट याचिकाकर्ताओं पर ऐसी राशि का दायित्व डालने से पहले, एक या दूसरे रिट याचिकाकर्ताओं को अवसर प्रदान किया जाना है।

29. हमारा विचार है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर व्यापक रूप से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किया जाना है, जिसका अर्थ है कि संबंधित पक्ष को पर्याप्त और पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए और वह पर्याप्त और पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए, जिससे संबंधित पक्ष को संपूर्ण रूप से दस्तावेज प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो, जो ऐसी मांग का आधार है।

30. यदि मांग नोटिस जारी करने के उद्देश्य से की गई गणना या लिए गए निर्णय का आधार प्रदान नहीं किया जा रहा है और निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न किए बिना केवल कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है, जो कि हमारे विचार से, संपूर्ण रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं माना

जा सकता है ताकि संबंधित पक्ष को पर्याप्त और पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा सके।

31. निरीक्षण रिपोर्ट की आपूर्ति न किए जाने के तथ्य को रिट याचिका के पैराग्राफ-16 में रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है।

32. राज्य ने जवाबी हलफनामा दायर किया है और रिट याचिका के पैराग्राफ-16, 20 और 21 में दिए गए बयान का जवाब देते हुए, जिसमें उल्लेखित निरीक्षण रिपोर्ट की आपूर्ति न किए जाने के तथ्य को स्पष्ट रूप से विवादित नहीं किया गया है। इसके अलावा, प्रतिवादी राज्य के विद्वान वकील ने यह प्रस्तुत करने में कोई संकोच नहीं किया कि निरीक्षण रिपोर्ट की आपूर्ति नहीं की गई है।

33. इसलिए, यह न्यायालय यह मानने में संकोच नहीं कर रहा है कि निरीक्षण रिपोर्ट की आपूर्ति न करके एक या दूसरे रिट याचिकाकर्ताओं को मांग नोटिस जारी करना, इसके सख्त पालन में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं कहा जा सकता है।

34. इसलिए, हमारा मानना है कि मांग नोटिस में हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक है।

35. तदनुसार, अनुलग्नक-1 श्रृंखला के रूप में संलग्न मांग नोटिस को रद्द कर दिया जाता है।

36. चूंकि हम प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन के आधार पर मांग नोटिस में हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसलिए यह अपेक्षित है कि मामले को जिला खनन अधिकारी, रांची के समक्ष भेजा जाए ताकि आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से दो सप्ताह के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध कराई जा सके, जिसे प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील द्वारा आज से तीन सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

37. निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि से चार सप्ताह की अवधि के भीतर एक या अन्य रिट याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से आपत्ति, यदि कोई हो, दर्ज करेंगे।

38. जिला खनन पदाधिकारी, रांची को निर्देश दिया जाता है कि वे उक्त आपत्ति पर प्रतिक्रिया प्राप्त होने की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर निर्णय लें।

39. इसमें यह उल्लेख करना आवश्यक है कि यदि कोई भी रिट याचिकाकर्ता जवाब देने में विफल रहता है, तो जिला खनन अधिकारी, रांची कानून के अनुसार निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे।

40. तदनुसार, इस रिट याचिका को उपरोक्त निर्देश/टिप्पणी के साथ स्वीकार किया जाता है।

41. मांग, जो रिट याचिका का विषय है, प्रमाण पत्र अधिकारी द्वारा लिए जाने वाले अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी, जैसा कि ऊपर निर्देशित है।

42. इस रिट याचिका के निपटारे के परिणामस्वरूप, लंबित अंतरिम आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद)

(न्यायमूर्ति नवनीत कुमार)

रोहित/-ए.एफ.आर.

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।